

[2023] 10 एस. सी. आर. 1:2023 आई. एन. एस. सी 583

/

पंजाब राज्य

बनाम

केवल कृष्ण

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 2128) 21 जून, 2023

/

[बी. वी. नागरत्ना और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 -धारा. 302-बरी होने की पुष्टि-विचारण न्यायालय का मामला कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ उसके अपने घर में शाम करीब 7 बजे जीवित देखा गया था-पीडब्लू-6, मृतक के भतीजे को मृतक का शव मिला-एफ. आई. आर. दर्ज की गई-आरोपी का नाम रिकॉर्ड में तब तक सामने नहीं आया जब तक कि पी. डब्ल्यू.-2, अंतिम देखी गई परिस्थिति का एकमात्र गवाह, न्यायालय में अपने बयान में कहता है कि उसने 13.12.1998 पर पुलिस के समक्ष आरोपी की संलिप्तता के संबंध में अपना संदेह व्यक्त किया था-यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने पी. डब्ल्यू.-3 से पहले अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी-आरोपी ने पुलिस को पी. डब्ल्यू.-3 में इस्तेमाल चाकू के बारे में खुलासा किया था। 302 - हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया-अपील पर, कहा: उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पीडब्लू-2 को पिछली बार देखी गई परिस्थिति के बारे में पता था और उसने ऐसा खुलासा किया था, तो पुलिस के लिए आरोपी के खिलाफ तब तक कार्रवाई नहीं करने का कोई कारण नहीं था जब तक कि 25.12.1998-इसलिए, पिछली बार देखी गई परिस्थिति की जानकारी देने के संबंध में पीडब्लू-2 का बयान संदिग्ध प्रतीत होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि गवाह को लिंक साक्ष्य बनाने के लिए स्थापित किया गया था-कथित तारीख और समय जब मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था, उस तारीख और समय से काफी दूर था जब मृतक मृत पाया गया था-इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरोपी कब घर से निकला था और इस बीच में कोई अन्य व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकता था, अपराध में किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ सहित अन्य मध्यवर्ती परिस्थितियों को अभियोजन पक्ष द्वारा खारिज नहीं किया गया था।

/

/

/

/

/

/

1 ए.

2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

अभियुक्त ने इस तरह का कोई भी स्वीकारोक्ति करने से इनकार किया-दोषपूर्ण परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे साबित नहीं हुईं और अन्यथा अंतिम बार देखी गई परिस्थिति भी अनिर्णायक थी, उच्च विचारण न्यायालय ने विचारण विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आदेश अपास्त करते हुए करने में न्यायसंगत ठहराया।

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-आयोजित: यह तुच्छ विधि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष को उन सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों में से प्रत्येक को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए जिन पर वह भरोसा करने का प्रस्ताव करता है; जिस परिस्थिति (परिस्थितियों) पर भरोसा किया गया है, वह निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए और अब तक एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इस निष्कर्ष से बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह अभियुक्त है और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जिसने अपराध किया था और उन्हें (यह) उसके अपराध से असंगत और उसकी निर्दोषता के अनुरूप अन्य सभी परिकल्पनाओं को बाहर करना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 106-साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को अभियोजन मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के अपने प्राथमिक बोझ का निर्वहन करने से दोषमुक्त नहीं करती है-यह केवल तभी होता है जब अभियोजन पक्ष ने सबूत का नेतृत्व किया होता है, जो यदि विश्वास किया जाता है, तो दोषसिद्धि को बनाए रखेगा, या जो प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, तो प्रश्न उन तथ्यों पर विचार करने के लिए उत्पन्न होता है जिनके सबूत का बोझ अभियुक्त पर होगा।

/

/

/

/

यू. पी. राज्य बनाम सहाय (1982) 1 एस. सी. सी. 352; एम. पी.

बनाम पल्टन मल्लाह (2005) 3 एस. सी. सी. 169:[2005] 1 एससीआर

710; बशीरा बेगम बनाम मोहम्मद इब्राहिम (2020) 11 एस. सी. सी.

174 :[2020] 3 एस. सी. आर. 562; शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 5 एस. सी. सी. 626-पर भरोसा किया गया।संदर्भित निर्णय

/

[2005] 1 एससीआर 710

पर विश्वास किया

पैरा **14**

[2020] 3 एससीआर 562

पर विश्वास किया

पैरा **15**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2014 की आपराधिक अपील सं. 2128।

/

2002 के सी. आर. एल. ए. सं. 372 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 01.05.2012 के निर्णय और आदेश से।

मोहित सिवाच, करण शर्मा, एड.अपीलार्थी के लिए।

/

3

पंजाब राज्य बनाम केवल कृष्ण ए

/

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

निर्णय

1. अपीलार्थी का वकील उपस्थित है।प्रत्यर्थी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है।कार्यालय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि एकमात्र प्रतिवादी को नोटिस दिया गया है, फिर भी उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

/

2. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री मोहित सिवाच को सुना है।

3. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (संक्षेप में उच्च न्यायालय) के 2002 की आपराधिक अपील संख्या 372 में दिए गए दिनांक 01.05.2012 के निर्णय और आदेश का

हवाला देती है, जिसके अंतर्गत निचली अदालत के निर्णय और आदेश में प्रतिवादी (केवल कृष्ण) को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और अपीलकर्ता (इसमें प्रतिवादी) को उन आरोपों से बरी कर दिया गया है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। 4. अभियोजन पक्ष का मामला निम्नलिखित परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य पर आधारित है:

/

/

(क) मृतक को आखिरी बार पीडब्लू-2 द्वारा आरोपी के साथ शाम लगभग 7 बजे अपने ही घर में जीवित देखा गया था।

(ख) मृतक के भतीजे पीडब्लू-6 को मृतक का शव उसके घर में लगभग दोपहर 1 बजे मिला।

/

(ग) लगभग 4.15 बजे आई. डी. 1 पर किए गए शव परीक्षण से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु दो दिनों के भीतर, सदमे और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप, पूर्व-शव परीक्षण घावों के कारण हो सकती थी।

/

(घ) अभियुक्त ने 25.12.1998 पर P.W-3 के सामने एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की और उसके बाद उसी दिन पुलिस को सौंप दिया गया।

/

(ई) अभियुक्त ने 25.12.1998 पर पुलिस को उस स्थान के संबंध में खुलासा किया जहां उसने अपराध में इस्तेमाल चाकू को छुपाया था, जिससे एक खंजर (चाकू) (Ex.P-1) बरामद हुआ। (च) शव परीक्षण सर्जन ने राय दी कि मृतक के शरीर पर पाए गए घाव उस खंजर के उपयोग के कारण हो सकते हैं।

/

/

/

[2023] 10 एस सी आर।

5. ट्रायल न्यायालय ने पाया कि वे परिस्थितियाँ साबित हुईं और एक श्रृंखला इतनी पूरी हो गई कि निर्णायक रूप से यह संकेत मिलता है कि यह आरोपी था और कोई और नहीं जिसने हत्या की और इस प्रकार दोषी ठहराया और आरोपी को तदनुसार सजा सुनाई।

6. अपनी दोषसिद्धि से व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

/

7. उच्च न्यायालय ने देखा कि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उसके खिलाफ उपस्थित होने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया था और दावा किया था कि उसे गलत निहितार्थ पर ही गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, विशेष रूप से पीडब्लू-2 द्वारा दिए गए बयान पर कि उसने पुलिस को आरोपी की संलिप्तता के बारे में खुलासा किया था, अपीलार्थी की गिरफ्तारी की तारीख (यानी, 25.12.1998) पर संदेह किया, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया गया था, और राय दी कि पीडब्लू-2 का बयान आरोपी के दावे को संभव बनाता है कि उसे 12.12.1998 पर ही गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि पीडब्लू-2 के साक्ष्य को अंतिम बार विश्वसनीय और विश्वसनीय नहीं पाया गया क्योंकि अगर पीडब्लू-2 पर आरोपी की संलिप्तता के संबंध में उसके संदेह के बारे में पुलिस को सूचित किया गया होता, तो पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लेती और आईडी-2 तक इंतजार नहीं करती। लेकिन रिकॉर्ड ने संकेत दिया कि आरोपी का नाम पहली बार 25.12.1998 पर सामने आया। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-2 को एक गवाह के रूप में अविश्वसनीय पाया, जिसे बाद में स्थापित किया गया था। अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने पाया कि अंतिम बार देखी गई परिस्थिति निर्णायक रूप से अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप सभी परिकल्पनाओं को छोड़कर उसके अपराध की ओर इशारा नहीं करती है, क्योंकि उस तारीख और समय के बीच एक बड़ा समय अंतराल था जब मृतक को आखिरी बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और मृतक के शव की खोज हुई थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस परिस्थिति पर ध्यान दिया कि 4.15 बजे आई. डी. 1 पर किए गए शव परीक्षण ने निचले अंगों पर कठोर मृत्यु की घटना का संकेत दिया, जिसमें सुझाव दिया गया कि मृत्यु शव परीक्षण के 30 घंटे के भीतर हो सकती है, जिससे मृत्यु की संभावना खुल जाती है। उपरोक्त पर ध्यान देते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि आरोपी मृतक के साथ नहीं रहता था और इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया था कि आरोपी के अलावा कोई और मध्यावधि में मृतक के घर में प्रवेश नहीं कर सकता था, अंतिम देखी गई परिस्थिति अनिर्णायक पाई गई।

/

/

/

/

/

/

/

पंजाब राज्य बनाम केवल कृष्ण ए

/

8. चाकू की बरामदगी की परिस्थिति के संबंध में, उच्च न्यायालय ने, सबसे पहले, गिरफ्तारी की तारीख पर संदेह किया, जैसा कि ऊपर देखा गया है, और दूसरी बात यह है कि यह पता लगाने के लिए कोई सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट नहीं थी कि क्या चाकू को मानव रक्त से रंगा गया था जो इसे अपराध से जोड़ता है। 9. उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में यह प्रदर्शित करने के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि आरोपी पी. डब्ल्यू. 3 के समक्ष स्वीकारोक्ति क्यों करेगा, विशेष रूप से, जब आरोपी का पी. डब्ल्यू.-3 के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं था और पी. डब्ल्यू.-3 उसकी मदद नहीं कर सकता था। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भी इस आधार पर संदेह किया गया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख (अर्थात्, 25.12.1998) संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि अभियुक्त के पहले गिरफ्तार किए जाने की उच्च संभावना थी, अर्थात्, 12.12.1998, जैसा कि उसने दावा किया था, क्योंकि पीडब्लू-2 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस को आरोपी की संलिप्तता के संबंध में उसके संदेह के संबंध में 13.12.1998 पर ही सूचित किया गया था।

/

/

10. ऊपर बताए गए साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि, सबसे पहले, दोषारोपण करने वाली परिस्थितियां उचित संदेह से परे साबित नहीं हुईं और दूसरी बात, वे इतनी पूरी श्रृंखला का गठन नहीं करती थीं कि निर्णायक रूप से यह संकेत दिया जा सके कि यह आरोपी था और किसी और ने, सभी मानवीय संभावनाओं में, अपराध नहीं किया था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और आरोपी को आरोप से बरी कर दिया।

/

/

11. राज्य (अपीलार्थी) के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त के साथ गवाहों की कोई सिद्ध शत्रुता नहीं थी। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित दोषपूर्ण परिस्थितियों के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर संदेह करने

का कोई अवसर नहीं था। ऐसी स्थिति में निचली न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि को उलटने का कोई औचित्य नहीं था। यह तर्क दिया गया कि मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था, आरोपी के साथ शराब पीते हुए, 10.12.1998 की शाम को और उसके बाद मृतक को किसी ने जीवित नहीं देखा था। शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु की संभावना लगभग उसी समय बताई गई है जब उसे आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था। इन परिस्थितियों में, यह साबित करने का भार अभियुक्त पर था कि उसने मृतक का साथ कब छोड़ा। इसके अभाव में, अन्य परिस्थितियों के साथ, अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय अपास्त करते हुए दिया और प्रतिवादी को बरी कर दिया।

/

/

/

/

/

[2023] 10 एस सी आर।

12. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

13. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, विधि पर ध्यान देना उचित होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आदेश को उलटते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना कब उचित होगा। इस संबंध में विधि अच्छी तरह से स्थापित है। आम तौर पर, यह न्यायालय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है। लेकिन जब यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने तर्क की पूरी तरह से गलत प्रक्रिया अपनाई है और मामले के तथ्यों के प्रति कानूनी रूप से गलत और विकृत दृष्टिकोण अपनाया है और कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की है, तो प्रतिवादी को बरी कर दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर और पर्याप्त विफलता हुई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र का सही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है (देखें -यू. पी. का राज्य बनाम सहाय (1982) 1 एस. सी. सी. 352)।

/

/

/

14. राज्य में एम. पी. बनाम.पल्टन मल्लाह, (2005) 3 एस. सी. सी. 169 इसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए यह देखा गया:

“8.....यह बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील होने के कारण, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमा होगा, जब तक कि साक्ष्य की विकृत सराहना नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हुई है और यदि उच्च न्यायालय ने एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लिया है तो यह न्यायालय अभियुक्त के पक्ष में पारित बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा और यदि दो विचार संभव हैं और उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिकोण चुना है जो न्यायसंगत और उचित है, तो भी यह न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। ”

/

/

15. बशीरा बेगम बनाम मोहम्मद में इस न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय में।इब्राहिम, (2020) 11 एस. सी. सी. 174, यह देखा गया:

“190. किसी निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को उलटने और अभियुक्त को बरी करने में सामान्य रूप से तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस तरह के उलटने/बरी करने को विकृति से दूषित नहीं किया जाता है।दूसरे शब्दों में, न्यायालय बरी करने के आदेश को उलट सकती है यदि न्यायालय को पता चलता है कि विधि में ठीक से प्रशिक्षित किसी भी व्यक्ति को रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विश्लेषण पर आरोपी को "दोषी नहीं" पाया जा सकता है। ”

/

/

7

पंजाब राज्य बनाम केवल कृष्ण ए

/

16. ऊपर उल्लिखित विधि के आलोक में, हमें जांच करनी होगी, सबसे पहले, क्या उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के किसी भी भौतिक टुकड़े को नजरअंदाज किया या गलत पढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है; दूसरा, क्या साक्ष्य की सराहना में कोई विकृति है; और, तीसरा, क्या उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है।

/

17. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है। यह तुच्छ विधि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष को उन सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों में से प्रत्येक को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए जिन पर वह भरोसा करने का प्रस्ताव करता है; जिस परिस्थिति (परिस्थितियों) पर भरोसा किया गया है, वह निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए और अब तक एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इस निष्कर्ष से बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह अभियुक्त है और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जिसने अपराध किया था और उन्हें (यह) उसके अपराध से असंगत और उसकी निर्दोषता के अनुरूप अन्य सभी परिकल्पनाओं को बाहर करना चाहिए।

/

18. तत्काल मामले में, हम रिकॉर्ड से देखते हैं कि मृतक का शव, जो अपने घर में नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, पहली बार मृतक के भतीजे पीडब्लू-6 द्वारा लगभग दोपहर 1 बजे पाया गया था। शव मिलने पर पीडब्लू-6 द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और पूछताछ आदि की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी का नाम 25.12.1998 तक रिकॉर्ड में सामने नहीं आया था, जब उसे कथित तौर पर पीडब्लू-3 द्वारा पीडब्लू-3 के सामने किए गए कबूलनामे पर पुलिस को सौंप दिया गया था। अंतिम बार देखी गई परिस्थिति के एकमात्र गवाह पीडब्लू-2 ने न्यायालय में अपने बयान में कहा कि उसने 13.12.1998 पर पुलिस के समक्ष आरोपी की संलिप्तता के संबंध में अपना संदेह व्यक्त किया था। उच्च न्यायालय ने राय दी कि यदि पीडब्लू-2 को पिछली बार देखी गई परिस्थिति के बारे में पता था और उसने ऐसा खुलासा किया था, तो पुलिस के लिए 25.12.1998 तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, अंतिम देखी गई परिस्थिति की जानकारी प्रदान करने के संबंध में पीडब्लू-2 का बयान संदिग्ध प्रतीत हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ कि गवाह को लिंक साक्ष्य बनाने के लिए स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि कथित तारीख और समय जब मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था, उस तारीख और समय से काफी दूर था जब मृतक मृत पाया गया था। निर्विवाद रूप से मृतक अपने ही घर में मृत पाया गया था जहाँ आरोपी नहीं रहता था। मृतक को कथित तौर पर आखिरी बार आरोपी के साथ शाम को लगभग 7 बजे 10.12.1998 पर जीवित देखा गया था, जबकि मृतक का शव 2 दिन बाद 12.12.1998 पर मिला था। शव परीक्षण

/

/

/

/

/

|

/

[2023] 10 एस सी आर।

रिपोर्ट, 12.12.1998 पर शाम लगभग 4.15 बजे किए गए शव परीक्षण के आधार पर, निचले अंगों में कठोर मृत्यु की घटना का उल्लेख किया गया है, जो शव परीक्षण के 30 घंटे के भीतर मृत्यु की संभावना को जन्म देता है, जिसका अर्थ है कि मृत्यु 10.12.1998 के शाम 7 बजे के बाद हुई होगी। ऐसी परिस्थितियों में, यह ध्यान में रखते हुए कि मृतक अपने ही घर में मृत पाया गया था, जहां आरोपी नहीं रहता था, और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरोपी कब घर से निकला था और इस बीच में कोई और घर में प्रवेश नहीं कर सकता था, अपराध में किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ सहित अन्य मध्यवर्ती परिस्थितियों को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा खारिज नहीं किया गया था। उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-2 की गवाही पर संदेह करने और अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप अन्य परिकल्पनाओं को छोड़कर उसके अपराध की ओर इशारा करने में अंतिम देखी गई परिस्थिति को अनिर्णायक पाते हुए न्यायसंगत ठहराया था।

/

/

19. जहां तक खंजर (चाकू) की बरामदगी का संबंध है, आरोपी ने इससे इनकार किया था और इसे अपराध से जोड़ने के लिए कोई सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए, अपने आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए इसका बहुत कम मूल्य था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों के आधार पर गिरफ्तारी की तारीख पर संदेह किया और परिस्थितियों पर विचार करने पर, अभियुक्त की गिरफ्तारी की संभावना को स्वीकार किया, जैसा कि अभियुक्त द्वारा दावा किया गया था, जो अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त द्वारा कथित रूप से 25.12.1998 पर किए गए प्रकटीकरण पर 25.12.1998 पर की गई वसूली संदिग्ध हो जाती है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को विकृत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

/

/

/

20. जहाँ तक अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य का संबंध है, वही पंचायत के एक सदस्य पीडब्लू-3 द्वारा प्रदान किया गया था, जहाँ मृतक रहता था। आम

तौर पर एक व्यक्ति या तो खुद को अपराध के बोझ से मुक्त करने के लिए या इस उम्मीद के अंतर्गत सुरक्षा लेने के लिए स्वीकार करता है कि जिस व्यक्ति के सामने स्वीकारोक्ति की जाती है वह उसकी रक्षा करेगा। आम तौर पर खुद को अपराध से मुक्त करने के लिए एक स्वीकारोक्ति उस व्यक्ति के सामने की जाती है जिस पर अपराध स्वीकार करने वाला विश्वास करता है। उच्च न्यायालय ने देखा कि यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि आरोपी का पीडब्लू-3 के साथ कोई पूर्व संबंध था या आरोपी ने पीडब्लू-3 से किसी भी मदद की उम्मीद की थी या मांगी थी और इसलिए, उसके सामने स्वीकारोक्ति की। विशेष रूप से, आरोपी ने इस तरह का कोई भी इकबालिया बयान देने से इनकार किया। ए के लिए

/

/

/

पंजाब राज्य बनाम केवल कृष्ण ए

उपरोक्त कारणों सहित अन्य, जिन्हें अभिलेख में रखने की आवश्यकता नहीं है, उच्च न्यायालय ने 25.12.1998 पर पीडब्लू-3 के समक्ष स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्त की परिस्थिति को खारिज कर दिया। अन्यथा भी, एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और केवल इसके आधार पर एक दोषसिद्धि को आम तौर पर दर्ज नहीं किया जाता है।

/

21. अपीलार्थी के विद्वान वकील का यह तर्क कि चूंकि अभियुक्त और गवाहों के बीच कोई सिद्ध शत्रुता नहीं थी, इसलिए उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, अपीलार्थी के लिए बहुत मददगार नहीं होगा क्योंकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामले में न केवल प्रत्येक दोषपूर्ण परिस्थितियों को उचित संदेह से परे साबित करना पड़ता है, बल्कि उन दोषपूर्ण परिस्थितियों को अब तक एक श्रृंखला का गठन करना चाहिए जो इस निष्कर्ष से कोई बचाव नहीं है कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह आरोपी है जिसने अपराध किया है और इसके अलावा, संचयी रूप से, उन्हें आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप और उसके अपराध से असंगत सभी परिकल्पनाओं को बाहर करना चाहिए। जैसा कि हमने पाया है कि दोषारोपण करने वाली परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई थीं और अन्यथा अंतिम बार देखी गई परिस्थिति भी अनिर्णायक थी, हमारे विचार में, उच्च विचारण न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आदेश अपास्त करते हुए करने में उचित ठहराया था।

/

/

22. यह तर्क कि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है और इसलिए, उसकी दोषसिद्धि उचित थी, गलत धारणा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अभियोजन मामले को साबित करने के अपने प्राथमिक बोझ का निर्वहन करने से मुक्त नहीं करती है। यह केवल तभी होता है जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य का नेतृत्व करता है, जो यदि माना जाता है, तो एक दोषसिद्धि को बनाए रखेगा, या जो एक प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, प्रश्न उन तथ्यों पर विचार करने के लिए उत्पन्न होता है जिनके सबूत का भार इन तथ्यों पर निर्भर करेगा -

/

/

अभियुक्त। (देखिए: शिवाजी चिंटप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021)

5 एससीसी 626)। यहाँ, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, सबसे पहले, दोषारोपण करने वाली परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे साबित नहीं हुईं और दूसरी बात, वे इतनी पूरी श्रृंखला नहीं बनाती हैं जिससे यह निश्चितता के साथ अनुमान लगाया जा सके कि यह आरोपी है और कोई और नहीं जिसने सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध किया है। इन परिस्थितियों में, अभियुक्त पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की सहायता से बोझ डालने या यह खुलासा करने का कोई अवसर नहीं था कि वह अपनी हत्या से पहले मृतक की कंपनी से अलग हो गया था।

/

/

10

/

[2023] 10 एस सी आर।

23. उपरोक्त सभी कारणों से, यह ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है और यह इंगित नहीं किया गया था कि किसी भी भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की गई थी या गलत तरीके से पढ़ा गया था, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा कारण नहीं पाते हैं।

24. तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

/

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।
(सहायक: महेन्द्र यादव, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/